



राष्ट्रदूत

Rashtradoot

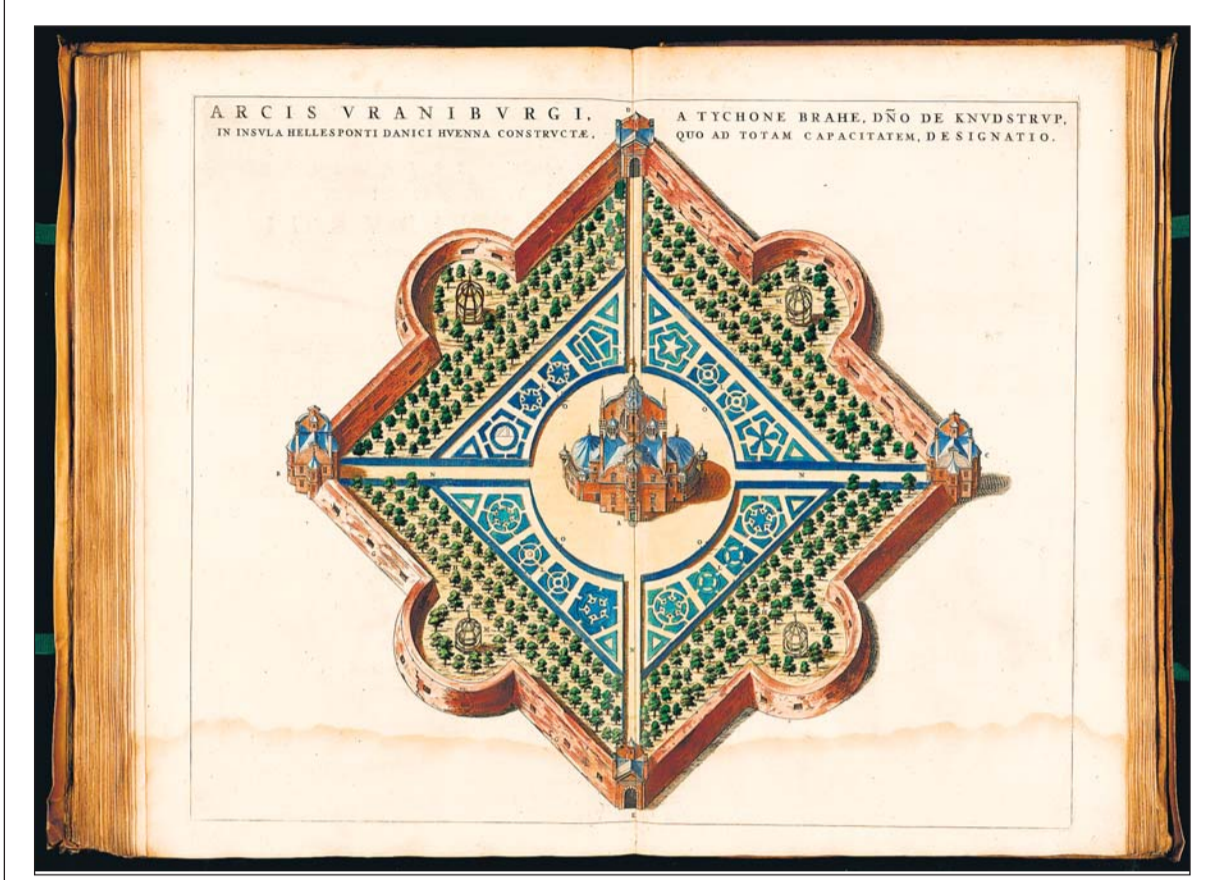
Metro

Salona Bandhan Rakhi Ka

After that, on every Salona (as Raksha bandhan was called) festival, she would come and tie a rakhi of pure pearls on Shah Alam II's wrist

Kuch Meetha Ho Jaaye!

Raksha Bandhan, a cherished festival that celebrates the bond of love and protection between siblings, calls for a joyous and sumptuous feast.



टैलिसकोप के अविष्कार से पहले खगोलविद् ब्रह्माण्ड के अध्ययन के लिए कई उपकरण व तकनीकें काम में लेते थे। इसमें सबसे सरल तरीका था बिना किसी उपकरण के सीधे ही आंखों से आकाश का अध्ययन। डैनमार्क के खगोलविद् टीको ब्राहे, दूरबीन के अविष्कार से पहले वाले युग के महानतम खगोलविद् थे। वे खगोलीय वस्तुओं और घटनाओं के सटीक ऑब्ज़र्वेशन के लिए विख्यात थे। उन्होंने ग्रहों और सितारों की स्थिति और गति पर काफी विस्तृत डेटा एकत्रित किया और पहला विस्तृत एवं सटीक कैटलॉग बनाया, जिसमें 1000 सितारों का उल्लेख था। यह कैटलॉग बाद के खगोलविदों के लिए भी काफी उपयोगी साबित हुआ। टीको ब्राहे के सिद्धांतों के आधार पर ही जर्मन गणितज्ञ और खगोलविद् जोहान्स कैपलर ने ग्रहों की गति के तीन नियम बनाए थे। बाद में इन्होंने के आधार पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम बने थे। ब्राहे की सेवाओं को सम्मानित करने के लिए सन् 1576 में डेनमार्क के राजा फ्रैडरिक द्वितीय ने उन्हें एक द्वीप दे दिया था, शोध व अध्ययन के लिए। ब्राहे ने वहां यूरेनिबोर्ग (वेधशाला) स्थापित की। दूरबीन के अविष्कार से पहले, यूरोप में पहली बार विशेषरूप से खगोल अध्ययन के लिए एक भवन बना था। सन् 1580 में यह बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। मुख्य इमारत के चारों तरफ चारदीवारी से घिरे बगीचे थे। मुख्य भवन तीन मंजिल का था। ग्राउण्ड फ्लोर पर ब्राहे व उनका परिवार और वहां आने वाले खगोलविद् रहते थे। दूसरी मंजिल पर खगोलशास्त्र के उपकरण थे। तीसरी मंजिल पर अग्रजों के कक्ष थे। किंग फ्रैडरिक द्वितीय की मौत के बाद ब्राहे को आर्थिक सहायता नहीं मिली, तो उन्होंने भी इस जगह को छोड़ दिया। सन् 1601 में उनकी मौत हो गई। नए राजा ने यूरेनिबोर्ग व एक अन्य एस्ट्रोलॉजिकल साइट को तोड़ दिया।

गहलोत उन 50 विधायकों को टिकट देना चाहते हैं, जिन्होंने उनके अनुसार उनकी सरकार बचाई थी

स्क्रीनिंग कमेटी इस बात का विरोध कर रही है, क्योंकि पार्टी द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार, इन विधायकों के जीतने की संभावना बेहद नगण्य है

रेणु मिश्र-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 अगस्त। राजस्थान कांग्रेस में चुनावी लड़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन 50 विधायकों के टिकट सुरक्षित करने के दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने उस समय उनका साथ दिया था, जब उनकी सरकार के लिये सचिन पायलट ने संकट खड़ा कर दिया था। गहलोत का कहना है कि इन विधायकों ने सरकार बचाई थी, इसलिए इनको टिकट दिया जाना चाहिये तथा इन्हें पुनः चुनाव में खड़ा किया जाना चाहिये।
लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोरोई ने तर्क दिया है कि पार्टी द्वारा किये गये सर्वे इन विधायकों की पराजय सुनिश्चित बना रहे हैं। गोरोई का कहना है कि पार्टी ऐसे लोगों को टिकट नहीं दे सकती, जिनकी हार सुनिश्चित हो।
ये लोग अत्यधिक भ्रष्ट लोगों की श्रेणी में भी हैं तथा जमीनी स्तर पर इनकी

स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोरोई के अनुसार, इन विधायकों में से अधिकतर विधायक बहुत ज्यादा "भ्रष्ट" हैं और जमीनी स्तर पर इनकी छवि "दागी" नेता की है।

कहा जा रहा है कि, राहुल गांधी अगर गहलोत के दबाव में आ गए तो पार्टी की स्थिति विकट होगी।

इस पूरे प्रकरण में रंधावा की स्थिति अटपटी है। वे अब तक गहलोत के भारी हिमायती के रूप में उभरे हैं तथा कई नेताओं, जैसे के.सी. विश्वनोई ने लिखित में उनके खिलाफ शिकायत की है।

अशोक गहलोत का प्रमुख प्रयास है कि, किसी भी तरह से सचिन पायलट के समर्थकों को टिकट न मिले, इसके लिए उन्होंने अपने खेमे के लोगों को टिकट वितरण प्रक्रिया में जोर-शोर से हंगामा करने के लिए एक्टिव कर दिया है।

अगर वे गहलोत के दबाव के आगे झुक जाते हैं तो पार्टी की स्थिति खराब हो जायेगी।
दिलचस्प बात यह है कि ए.आई.सी.सी. महासचिव सुब्रजिंदर रंधावा की स्थिति बेहद अटपटी है वे मुख्यमंत्री गहलोत के भारी हिमायती के रूप में उभरे हैं। और उनकी छवि एवं प्रतिष्ठा पूरी तरह गत में जा चुकी है क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री की आती है, तो वे खराब से खराब समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
बहुत से पार्टी पदाधिकारियों ने उनके खिलाफ शिकायतें भी की हैं। शिकायतकर्ताओं ने पूर्व विधायक तथा "दुर्जा प्राप्त मंत्री" के.सी. विश्वनोई भी शामिल हैं, जिन्होंने रंधावा के खिलाफ लिखित शिकायत भेजी है।
अगर वे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सुबह का समय मांगते हैं, तो गहलोत उन्हें शाम को बुलाते हैं तथा फिर उन्हें टाल देते हैं।
(शेष पृष्ठ 4 पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है?
ऑटोमैटिक **कान की मशीनों** स्पीच थेरेपी
कॉकलियर इम्प्लांट, ऑटिजम डिज़ेस, हकलाना, तुतलाना
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR, Vaishali Nagar, JAIPUR
सम्पर्क: **94602 07080**

'लोकसभा चुनाव निर्धारित समय से पूर्व दिसम्बर में हो सकते हैं'

प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार ने भी यही बात कही

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 अगस्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वही बात दोहराई, जो कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही थी कि लोकसभा चुनाव कुछ महीने पहले करवा दिए जाएंगे और दिसंबर में चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही होंगे। क्या बनर्जी और कुमार लोकसभा चुनाव जल्दी होने की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि इंडिया गठबंधन के नेताओं में रणनीतियों को जल्दी अंतिम रूप देने की भावना जागे? या वास्तव में यह संभावना है कि केन्द्र सरकार चुनाव आयोग को जल्दी चुनाव घोषित करने के लिए उकसाएगा?
चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों से उजागर हुआ है कि भाजपा मूल्य वृद्धि और बरोजगारी के कारण मतदाताओं पर

कड़ा खो रही है। सर्वेक्षण के नतीजे यह भी बताते हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बहुत कमजोर रहेगा जबकि राजस्थान में (शेष पृष्ठ 4 पर)

चर्चा है कि, क्या बनर्जी और कुमार इसलिए ऐसी संभावना जता रहे हैं ताकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बिना देरी के जल्द से जल्द रणनीतिको अंतिम रूप दे दें।
हालांकि यह भी चर्चा है कि, दिसम्बर में जिन चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए भाजपा की केन्द्र सरकार लोकसभा चुनाव भी दिसम्बर में करवा सकती है।
कहा जा रहा है कि, लोकसभा चुनाव हुए तो भाजपा को लाभ होगा, क्योंकि चन्द्रयान-3 की सफलता और मोदी की लोकप्रियता के आधार पर इन चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की स्थिति बेहतर हो सकती है।

'ई.डी. का मतलब है "एक्सटॉर्शन" डिपार्टमेंट'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 अगस्त। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बंद करने की गुहार करते हुए कहा कि, यह

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि, ई.डी. (एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट) को बंद कर दिया जाए, जो भाजपा का "एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट" बन गया है।

सत्तारूढ़ भाजपा का "एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट" बन गया है।
संजय सिंह ने यह टिप्पणी, सी.बी.आई. द्वारा ई.डी. अधिकारियों के विरुद्ध दायर एफ.आई.आर. के बाद (शेष पृष्ठ 4 पर)

चुनावी लड़ाई में प्रत्याशी की बहन पर घटिया आरोप

-लक्ष्मण बैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 अगस्त। केरल के विधानसभा क्षेत्र पुयुपल्लू, जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के पुराने एवं दिग्गज नेता ओमन चान्डी कर रहे थे, के लिये हो रहे उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन "इंडिया" के पार्टनर-कांग्रेस एवं वामदलों के बीच की लड़ाई बढ़े ही घटिया स्तर पर पहुंच गई है। और तो और, दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री की छोटी पुत्री तक पर गंदे एवं निन्दनीय हमले किये जा रहे हैं।
ओमन चान्डी के निधन के कारण होने जा रहा यह उपचुनाव मूलतः द्विपक्षीय ही है तथा सत्तारूढ़ वामपंथी मोर्चा विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यू.डी.एफ. से इस सीट को जीतने के लिये एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है। प्रसंगवश बता दें कि ओमन चान्डी के पुत्र चान्डी ओमन (जी हाँ, उनका यही नाम है) सी.पी.एम. के जैक सी थॉमस के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यूँ तो चुनावी लड़ाई टक्कर की है लेकिन कांग्रेस का पलड़ा कुछ भारी नजर आ रहा है।

यह नजारा दिखा केरल में स्व. ओमन चान्डी की सीट पर हो रहे उप चुनाव में, जहां से चान्डी के बेटे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।

इस उप चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का स्तर बेहद गिर गया है। वामपंथी दलों ने चान्डी की छोटी बेटी पर घटिया आरोप लगाए हैं, जबकि वे चुनाव में प्रत्याशी भी नहीं हैं। चान्डी की बेटी ने इस पर पुलिस में रिपोर्ट की है।

गौरतलब है कि, कांग्रेस और वामपंथी, दोनों इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। कहा गया है कि, गठबंधन के सभी दल विधानसभा में आमने-सामने तो हो सकते हैं, पर चुनावी मुकाबला सद्भाव पूर्ण होना चाहिए।

यहां प्रचार बहुत घृणित स्थिति में पहुंच गया है तथा चान्डी परिवार के राजनैतिक विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार की बहिन तथा पूर्व मुख्यमंत्री की छोटी बेटी अचू ओमन पर तीखे तथा घृणित हमले कर रहे हैं। अचू ओमन ने साइबर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें उन पर हो रहे साइबर हमलों तथा घृणित सोशल मीडिया अभियान का हवाला दिया गया है, जिसमें, उन पर झूठे आरोप लगाते हुये, उनकी तथा उनके पिता एवं परिवार की छवि को खराब किया जा रहा है। उन्होंने अपनी शिकायत में तिरुवनंतपुरम-निवासी एक व्यक्ति का नाम भी दिया है, जिसने अपने फेसबुक अकाउंट पर उनके खिलाफ निन्दनीय टिप्पणियाँ पोस्ट की हैं। विधिवत दर्ज कराई गई, इस शिकायत में, अचू ओमन ने कहा है कि "आरोपी ने दुर्भावनापूर्ण तथा निन्दनीय इरादे से जनता से सोडिश्य झूठ बोला है ताकि शिकायतकर्ता (शेष पृष्ठ 4 पर)

सेवानिवृत्त आई.ए. एस. राजीव महर्षि आई.सी.यू. में भर्ती

जयपुर, 29 अगस्त (का.सं.)। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व सी.ए.जी. राजीव महर्षि सोमवार को साइकिल से गिरने पर सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जे.एल.एन. मार्ग पर मोती दूंगरी स्थित सोनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

महर्षि सोमवार को साइकिल से गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोट आई।

फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर है और आईसीयू में इलाज चल रहा है।
डॉ. विमल सोनी, न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राघवेंद्र चौधरी और उनकी टीम की देखरेख में महर्षि का इलाज हो रहा है। डॉ. सोनी ने बताया कि, महर्षि को गंभीर हालत में सोनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वे अस्पताल आए थे, तब सिर में चोट लगने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो रही (शेष पृष्ठ 4 पर)

जात आधारित जनगणना को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है इंडिया

इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता अलग-अलग बयानों में जात आधारित जनगणना करवाने का वादा कर रहे हैं

इंडिया गठबंधन के नेताओं का मत है कि, भाजपा के हिन्दुत्व मुद्दे को जात आधारित जनगणना से ही मात दी जा सकती है।

भाजपा एवं संघ परिवार जात आधारित जनगणना के खिलाफ है, क्योंकि वो जानते हैं कि, इससे उनका हिन्दुत्व मुद्दा कमजोर पड़ेगा, पर वे इस दुविधा को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से कतराते हैं।

भाजपा की यह दुविधा तब जाहिर हुई, जब, बिहार सरकार के कास्ट सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में केन्द्र सरकार ने जो हलफनामा दिया था, उसे तुरंत ही वापिस ले लिया और नया हलफनामा दर्ज किया।

भाजपा की केन्द्र सरकार ने पहले शपथ पत्र में लिखा था कि, जनगणना या ऐसी कोई गतिविधि सिर्फ केन्द्र सरकार कर सकती है। बाद में दर्ज शपथ पत्र में वह पैराग्राफ हटा लिया गया था।

आर.एस.एस. इस प्रकार की जातीय जनगणना के खिलाफ है, क्योंकि इससे उनका हिंदुत्व का आधार कमजोर पड़ जाएगा, हालांकि वे अपनी दुविधा सार्वजनिक नहीं कर पाते।
यह दुविधा उस समय उभर कर सामने आई जब केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार द्वारा जातीय सर्वेक्षण करवाने के निर्णय पर हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया है कि केवल केंद्र सरकार ही जनगणना या उससे मिलती जुलती कार्रवाई कर सकती है।
कुछ घंटों बाद केंद्र सरकार ने नया हलफनामा दायर किया जिसमें यह

टिप्पणी हटा ली गई। इसमें कहा गया है कि वह पैराग्राफ "अनजाने में आ गया"।
विपक्ष ने तुरंत आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा कुछ घंटों में किए गए इस सुधार ने भाजपा तथा उसके द्वारा सर्वेक्षण रोकने के इरादे की पोल खुल गई है।
एक के बाद एक शपथ पत्रों ने काफी विवाद पैदा कर दिया और जद (यू) तथा उसके सहयोगी राजद ने भाजपा पर हमला बोला।
राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय जातीय सर्वेक्षण को रोकने के लिए हरसंभव दांव आजमा रहा है। उन्होंने कहा, "इससे यह सोशल मीडिया अभियान का हवाला दिया गया है, जिसमें, उन पर झूठे आरोप लगाते हुये, उनकी तथा उनके पिता एवं (शेष पृष्ठ 4 पर)

पूर्व प्रधानमंत्री वसुंधरा राजे की पूरे राज्य में अच्छी पकड़ है, इसलिए भाजपा नेतृत्व मजबूत राजे की सलाह पर टिकट देने को बाध्य है।

करना है।
पार्टी पहले उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगी जहां पार्टी पिछली बार हार गई थी। इन सीटों की संख्या 125 है। और सितम्बर के इनमें 50 सीटों पर 40 प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। इनमें से आधे से ज्यादा वसुंधरा राजे के करीबी (शेष पृष्ठ 4 पर)

एडवोकेट नकवी अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 अगस्त। एक और जहाँ आम चुनाव जल्दी होने के अपुष्ट समाचारों पर लोग विश्वास करने लगे हैं वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया जातिगत जनगणना पर चर्चा करने जा रहा है ताकि इसे चुनावी मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके।
22 अगस्त का मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने वादा किया कि अगर लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जातिगत जनगणना होगी।
सूत्रों ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की सारी पार्टियाँ इस विचार का समर्थन कर रही हैं और इंडिया गठबंधन जनता के सामने संदेश ले जाने के लिए चर्चा के बिंदु तैयार करेगा। भाजपा और

नकवी हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में राज्य सरकार की पैरवी करेंगे।

हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में राज्य सरकार की ओर से मुकदमों में पक्ष रखेंगे। अधिवक्ता नकवी वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक भी अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं।

